INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

MPPSC-PCS

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

भाग – 4

भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स **"MPPSC -PCS (Madhya Pradesh Public Service Commission) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)"** को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"संयुक्त राज्य / अपर अधीनस्थ सेवा (PCS)"** भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/dy0fu7

Online Order करें - https://bit.ly/3BGkwhu

मूल्य : ₹	**संस्करण : नवीनतम**

भारतीय अर्थव्यवस्था		
क्र.सं.	अध्याय	पेज
1.	अर्थशास्त्र की विशेषताएं • परिचय • अर्थव्यवस्था के प्रकार • अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक • भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं	1
2.	राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएँ • सकल घरेलू उत्पाद • शुद्ध घरेलू उत्पाद • सकल राष्ट्रीय उत्पाद • शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद • हरित राष्ट्रीय आय • राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग • राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में अंतर • राष्ट्रीय आय का मापन • राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ • राष्ट्रीय आय की गणना का महत्त्व	5
3.	विकसित भारत @2047 • वर्तमान स्थिति • योगदान • प्रमुख कारक • भविष्य में अर्थव्यवस्था में आने वाली चुनौतियाँ	12
4.	आर्थिक संवृद्धि एवं विकास • आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर • आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक	13

5.	आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएं • सतत विकास लक्ष्य • सरकार की पहलें • नीति आयोग • अटल नवप्रवर्तन मिशन	15
6.	वित्तीय संस्थाएं (बैंकिंग) • बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास • भारत में बैंकों का वर्गीकरण • भारतीय रिज़र्व बैंक • भारतीय स्टेट बैंक • वाणिज्यिक बैंक • भारतीय औद्योगिक विकास बैंक • भारत में विदेशी बैंक • गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं • बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियाँ • बैंक बोर्ड ब्यूरो • भारत में बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश से सम्बंधित नियम • NPA की समस्या • वित्तीय समावेशन • सेबी • मुद्रा एवं इसके प्रकार	24
7.	प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न • कृषि के अन्य प्रकार एवं प्रतिरूप • भारत की फसल ऋतुएँ	46

	• प्रमुख फसलें • हरित क्रान्ति • कृषि और संबंधित क्षेत्रों का अवलोकन • किसानों की आय को दोगुना करने हेतु कार्य योजना • कृषिगत सुधार • कृषि के समक्ष चुनौतियाँ • घटती उत्पादकता • किसान संकट • सरकारी पहल और विभिन्न योजनाएं • पीएम किसान, एनएमएसए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि • कृषि मूल्य नीति ,विपणन और वित्त • कृषि लागत तथा मूल्य आयोग (ACPC) • मूल्य वर्धन के लिए कृषि स्टार्ट अप और कृषि प्रसंस्करण	
8.	भारत में औद्योगिक नीतियाँ और औद्योगिक विकास • औद्योगिक नीति का अर्थ • औद्योगिक नीति का विकास • औद्योगिक नीति, 1948, 1956, 1991 • औद्योगिक नीति का मूल्यांकन • औद्योगिक वित्त • भारत के प्रमुख उद्योग	62
9.	भारत में आर्थिक सुधार • उदारीकरण,निजीकरण , वैश्वीकरण	76
10.	भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां • कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान	79

11.	आतिथ्य और पर्यटन • विदेशी मुद्रा आय में योगदान	85
12.	भारत में वस्तु व सेवाओं का मानकीकरण • भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम • बीका उद्देश्य .एस.आई. • क्षेत्रीय कार्यालय	90
13.	राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ • लोक व्यय • भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व • मौद्रिक नीतियाँ एवं वित्तीय समावेशन • बजट एवं बजट निर्माण • बजट के प्रकार • घाटा प्रबंधन • जेंडर बजटिंग • बजट 2024-25 • भारत में कराधान • वस्तु एवं सेवा कर (GST) • अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नकद लेनदेन का प्रभाव	92
14.	खाद्य सुरक्षा एवं लोक वितरण प्रणाली	112
15.	गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन • भारत में गरीबी का आकलन • भारत में निर्धनता से सम्बंधित समितियां • राष्ट्रीय बहु आयामी गरीबी सूचकांक - • बेरोजगारी	117

	• बेरोजगारी के कारण • भारत में क्षेत्रीय असंतुलन	
16.	विदेश व्यापार नीतियाँ एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान • 20 –G • सार्क • SAFTA • आसियान • अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) • विश्व बैंक • ए.डी.बी. • विश्व व्यापार संगठन की भूमिका	127
	मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था	
1.	मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधन • मध्य प्रदेश जनसंख्या नीति • शिक्षा ,स्वस्थ्य ,एवं कौशल • अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का प्रभाव • जनसंख्या वृद्धि के परिणाम	134
2.	मध्यप्रदेश अर्थव्यवस्था के नवीनतम बिंदु • भारतीय अर्थव्यवस्था में MP की वर्तमान स्थिति • राज्य घरेलू उत्पाद • प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि • राज्य का राजस्व व्यय ,व्यय एवं ऋण • राजकोषीय अनुशासन • केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा • सतत विकास लक्ष्यों में मध्यप्रदेश की प्रगति	139

	• आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश • एक जिला एक उत्पाद (ODOP) • मध्य प्रदेश में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की प्रगति	
3.	मध्य प्रदेश में उद्यानिकी • पशुधन • डेयरी • मत्स्य पालन	150
4.	पर्यटन, व्यापार, और निवेश प्रोत्साहन • नीतिगत पहलें • वित्तीय आवंटन • व्यापार • निर्यात	150
5.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए नीतियाँ • वन नीति • जल नीति • खनिज नीति	154
6.	वित्तीय और सामाजिक समावेशन	158
7.	मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास • राज्य का आर्थिक वर्गीकरण • मध्यप्रदेश में ग्रामीण व शहरी विकास • कृषि, प्रमुख फसलें तथा जोत • मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र • खाध्य सुरक्षा एवं वितरण प्रणाली • प्रमुख उद्योग MSME एवं अधोसंरचना का विकास • मध्य प्रदेश की जातियाँ	160

	• अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ • मध्य प्रदेश की योजनाएँ एवं कल्याणकारी कार्यक्रम	
४.	सांख्यिकी, डाटा विश्लेषण और प्रायिकता	।९।
९.	प्रायिकता	।९।

अर्थशास्त्र

अध्याय – I

अर्थशास्त्र की विशेषताएं

परिचयः-

- Economics (अर्थशास्त्र) शब्द एक Greek word ' Oikonomia ' से उत्पन्न हुआ है ।
- Oikonomia शब्द Oikos and Nomos दो शब्दों से मिलकर बना है ।
- Oikos का अर्थ गृह अथवा परिवार जबकि Nomos का का अर्थ है प्रबंधन । अर्थात् Oikonomia गृह प्रबंधन की प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है ।

अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर?:-

अर्थशास्त्र	अर्थव्यवस्था
अर्थशास्त्र के अंतर्गत विषय और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है	अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
अर्थशास्त्र केवल अध्ययन का क्षेत्र है	अर्थव्यवस्था निष्पादन (Execution) की भूमिका निभाती है।
अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है इनकी किताब (The Wealth of nations) मे अर्थव्यवस्था का विस्तार किया है।	जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं ।
अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं- (i) व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics) (ii) समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)	अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था।
	अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यावहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि ।

अर्थशास्त्र की शाखाएँ (Branches of economic)

- अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं-

(i) व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics)
(ii) समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)

अर्थव्यवस्था के प्रकारः-

A. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy):-

- जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है उसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।
- अर्थात् यहाँ आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है।
- एडम स्मिथ की **'दा वेल्थ ऑफ़ नेशन'** पूँजीवाद को दार्शनिक आधार प्रदान करता है। अमेरिका समेत पश्चिमी यूरोपीय देश पूँजीवाद के समर्थक है।

पूँजीवाद के फायदे या गुणः-

- पूँजीवाद नवाचार को बढ़ावा देता है।
- पूँजीवाद और समान दोनों स्वतंत्रता और अवसर पर केंद्रित हैं।
- पूँजीवाद आबादी की जरूरतों को पूरा करता है।
- पूँजीवाद स्व-नियामक है।
- पूँजीवाद समग्र रूप से समाजों की मदद करता है।

पूँजीवाद के नुकसान या दोषः-

- धन और आय के वितरण की असमानता
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अपरिहार्य के रूप में कक्षा संघर्ष
- सामाजिक लागत बहुत अधिक है
- पूँजी अर्थव्यवस्था की अस्थिरता
- बेरोजगारी और रोजगार के तहत
- वर्किंग क्लास में पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं है ।

B. समाजवाद अर्थव्यवस्था

- उत्पादन एवं वितरण के सामूहिक नियंत्रण पर बल देता है।
- राज्य द्वारा विनियमित निजी क्षेत्र की भूमिका से लोक कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति।
- भारत,बांग्लादेश,ब्राजील,समेत विकासशील अधिकांश देश समाजवाद के समर्थक हैं।
- बौद्ध और जैन धर्म का अस्तेय आवश्यकता से अधिक संसाधनों के एकत्रीकरण का विरोध करता है, जो समाजवाद की अवधारणा के अनुकूल है।
- अशोक के शिलालेखो से लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती हैं, वहीं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सुदर्शन झील के निर्माण के संदर्भ में प्रमाण देता है।
- इसी प्रकार मध्यकाल में फिरोजशाह तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण, बेरोजगारों के लिए पेंशन जैसी समाजवादी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है।

समाजवाद के पक्ष में तर्क या गुणः-

शोषण का अन्तः-

- समाजवाद श्रमिको एवं निर्धनो के शोषण का विरोध करता है। इसलिये विश्व के श्रमिक किसान निर्धन इसका समर्थन करते है।

सामाजिक न्याय पर आधारित:-

- समाजवादी व्यवस्था में किसी वर्ग विशेष के हितो को महत्व न देकर समाज के सभी व्यक्तियों के हितो को महत्व दिया जाता है यह व्यवस्था पूँजीपतियों के अन्याय को समाप्त करके एक ऐसे वर्गविहीन समाज की स्थापना करने का समर्थन करती है जिसमें विषमता न्यनूतम हो।

उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यक्ता:-

- व्यक्तिवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किये जाने वाले उत्पादन के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था में समाजिक आवश्यक्ता और हित को ध्यान में रखकर उत्पादन होगा क्योंकिसमाजवाद इस बात पर बल देता है कि जो उत्पादन हो वह समाज के बहुसख्यक लोगो के लाभ के लिए हो।

उत्पादन पर समाज का नियंत्रण :-

- समाजवादियो का मत है कि उत्पादन और वितरण के साधनो पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करके विषमता को समाप्त किया जा सकता है।
- सभी को उन्नति के समान अवसर
- साम्राज्यवाद का विरोधी

समाजवाद के विपक्ष में तर्क अथवा आलोचना :-

राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि :-

- समाजवाद मे आर्थिक तथा राजनीतिक दोनो क्षेत्रों में राज्य का अधिकार होने से राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप राज्य द्वारा किये जाने वाले कार्य समुचित रूप से संचालित और समपादित नहीं होंगे।

वस्तुओं के उत्पादन में कमी :-

- समाजवाद के आलोचको की मान्यता है कि यदि उत्पादन के साधनो पर सम्पूर्ण समाज का नियंत्रण हो तो व्यक्ति की कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जायेगी और कार्यक्षमता भी धीरे धीरे घट जायेगी।
- व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा तो वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा घट जायेगी।

समाजवाद प्रजातंत्र का विरोधी :-

- प्रजातंत्र में व्यक्ति के अस्तित्व को अत्यंत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है वही समाजवाद में वह राज्य रूपी विशाल मशीन में एक निर्जीव पूर्जा बन जाता है।

नौकरशाही का महत्व :-

- समाजवाद में राज्य के कार्यो में वृध्दि होने के कारण नौकरशाही का महत्व बढ़ता है। और सभी निर्णय सरकारी कर्मचारियो द्वारा लिये जाते है ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार बढ़ता है।

समाजवाद हिंसा को बढ़ाता है :-

- समाजवाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी तथा हिंसात्मक मार्ग को अपनाता है। वह शांतिपूर्ण तरीको में विश्वास नहीं करता।
- वह वर्ग संघर्ष पर बल देता है। जिसके परिणामस्वरूप समाज में वैमनस्यता और विभाजन की भावना फैलती है।
- पूर्ण समानता संभव नहीं।

C. मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) :-

- यहाँ, उत्पादन की कुछ योजनाएँ राज्य द्वारा सीधे या इसके राष्ट्रीयकृत उद्योगों के माध्यम से शुरू की जाती है, और कुछ को निजी उद्यम के लिए छोड़ दिया जाता है।
- इसका अर्थ है कि समाजवादी क्षेत्र (यानी सार्वजनिक क्षेत्र) और पूँजीवादी क्षेत्र (यानी निजी क्षेत्र) दोनों एक-दूसरे के साथ हैऔर एक-दूसरे के पूरक है।
- इसे बाजार की अर्थव्यवस्था और समाजवाद के बीच आधे घर के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थान आर्थिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। इसलिए, इस प्रकार कीअर्थव्यवस्था पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के लाभों को सुरक्षित करने का प्रयास करती है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था के फायदे:-

निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन :-

- मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करता है और इसे बढ़ने का उचित अवसर मिलता है।
- यह देश के भीतर पूँजी निर्माण में वृद्धि की ओर जाता है।

स्वतंत्रता:-

- मिश्रित अर्थव्यवस्था में, पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक और व्यावसायिक दोनों तरह की स्वतंत्रता है।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है।
- इसी तरह, हर निर्माता उत्पादन और खपत के संबंध में निर्णय ले सकता है।

संसाधनों का इष्टतम उपयोग:-

- इस प्रणाली के तहत, निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए काम करते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक लाभ के लिए काम करता है जबकि निजी क्षेत्र लाभ के अधिकतम करण के लिए इन संसाधनों का इष्टतम उपयोग करता है।

आर्थिक योजना के लाभ:-

- मिश्रित अर्थव्यवस्था में, आर्थिक योजना के सभी फायदे हैं। सरकार आर्थिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने और अन्य आर्थिक बुराइयों को पूरा करने के लिए उपाय करती है।

कम आर्थिक असमानताएँ:-

- पूँजीवाद आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है लेकिन एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत, सरकार के प्रयासों से असमानताओं को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

- खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना प्रतिबंध के वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है ।
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वतंत्र रूप से होता है ।
- व्यवसायिक बौद्धिक पूँजी के स्वामित्व को ट्रेड मार्क कहा जाता है ।
- निर्माण एवं विनिर्माण वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र,वानिकी मत्स्यन तथा खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ।
- वर्ष 1776 में एडम स्मिथ द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' थी ।
- बैंकिंग बीमा चिकित्सा शिक्षा पर्यटन आदि तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं ।
- भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण यहाँ से आधिक्य की स्थिति रहती है ।
- **NOTE-** अमेरिकी थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। वर्ष 2018 में भारत 7वें नंबर पर था।

अभ्यास प्रश्न

1. व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है।
(A) विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन।
(B) संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन
(C) कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन
(D) इनमें से कोई नहीं। **(A)**

2. निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है?
(A) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में
(B) समाजवादी अर्थव्यवस्था में
(C) मिश्रित अर्थव्यवस्था में
(D) अविकसित अर्थव्यवस्था में **(B)**

3. अर्थशास्त्र के जनक कौन थे?
(A) एडम स्मिथ (B) जॉन रॉबिंसन
(C) अरस्तु (D) प्लेटो
(A)

4. अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector of Indian Economy) में किसे शामिल नहीं किया जाता है ?
(A) पशुपालन
(B) होटल
(C) खनन एवं उत्खनन
(D) वन एवं वानिकी **(B)**

5. बंद अर्थवयवस्था (Closed economy) वह अर्थवयवस्था है जिसमे -
(A) मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है
(B) घाटे की वित्त वयवस्था होती है
(C) केवल निर्यात होता है
(D) न तो निर्यात होता है, न आयत होता है **(D)**

6. निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान करे

पुस्तक	लेखक
(A) दास कैपिटल	कार्ल मार्क्स
(B) फ्री ट्रेड टुडे	पी. एन. भगवती
(C) प्लानिंग एण्ड द पुअर	बी. एस. मिन्हास
(D) एशियन ड्रामा	गुर्नार मिर्डाल **(B)**

7.अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतया विशेषता होती है-
(I) प्रति व्यक्ति निम्न आय
(II) पूँजी निर्माण की निम्न दर
(III) निम्न आश्रितता अनुपात
(IV) तृतीयक क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना
नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए
कूट:
(A) I तथा II
(B) II तथा III
(C) III तथा IV
(D) I तथा IV **(A)**

8. मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है -
(A) वृहत् एवं कुटीर उद्योगों का सहअस्तित्व
(B) औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग
(C) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं **(C)**

9. वर्तमान में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में कौन-से स्थान पर है?
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 7 **(C)**

10. अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है?
(A) एडम स्मिथ
(B) कौटिल्य
(C) मेगस्थनीज
(D) इसमें से कोई नहीं **(D)**

अध्याय – 5

आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजनायें

अर्थव्यवस्था में राज्य की तीन भूमिकाएँ स्पष्ट होती हैं।

1. अर्थव्यवस्था के नियामक (regulator) की भूमिका, जिसके अंतर्गत राज्य प्रमुख आर्थिक नीतियाँ बनाता है और उनका कार्यान्वयन करता है। आर्थिक नियामक की भूमिका पूँजीवादी, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था तीनों ही में राज्य के पास रहा है।
2. 'निजी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकर्ता और आपूर्तिकर्त्ता की भूमिका जिसके अंतर्गत राज्य अपनी भूमिका का दो रूप में निर्वाह कर सकता है प्रथम रूप जिसके अंतर्गत इन उत्पादों को नागरिकों तक बिना किसी मूल्य के आपूर्ति की जाती है, जैसा कि राज्य अर्थव्यवस्थाओं (समाजवादी और साम्यवादी) में होता था। दूसरे रूप में राज्य इन उत्पादों को उपभोक्ता तक बाजार व्यवस्था के अनुसार पहुंचाता है जैसा कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान में दिखता है जहाँ सरकारी कंपनियाँ निजी कंपनियों की तरह यह कार्य लाभ या फिर कुछ सब्सिडी देकर कर रही हैं।
3. 'लोक वस्तुओं या 'सामाजिक वस्तुओं (social goods) के आपूर्तिकर्ता की भूमिका, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, इत्यादि सुविधाओं का जनता को सरकार द्वारा बिना किसी भुगतान का पहुंचाया जाता है। इनका भुगतान पूरी अर्थव्यवस्था (सरकार) करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य यह भूमिका नहीं निभाता था।

   विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं अपनी सामाजिक-राजनीतिक विचारधाराओं के मुताबिक अपने राज्य के लिए विभिन्न भूमिकाएँ तय करती हैं। अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए दुनिया में अलग-अलग सिद्धांत अपनाएँ जाते हैं, इस वजह से अतीत में विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई।

   अर्थव्यवस्था के नियमन पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि सभी तरह की अर्थव्यवस्थाओं में सरकार ही उसे नियमित करती हैं। लेकिन राज्यों की ओर से दो अन्य गतिविधियों के चयन की वजह से वास्तिवक अंतर पैदा होता है। जिस अर्थव्यवस्था में दोनों भूमिकाएं (ii और iii) सरकार के अधीन होती हैं उन्हें सरकारी अर्थव्यवस्थाएँ कहते हैं। इसमें दो तरह की अर्थव्यवस्थाएँ होती है समाजवादी और दूसरी साम्यवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में श्रम सरकार के अधीन नहीं होता, लेकिन उनका शोषण सरकार नहीं कर सकती है। जबकि साम्यवादी (कम्यूनिस्ट) अर्थव्यवस्था में श्रम सरकार के अधीन होता है। इन दोनों अर्थव्यवस्था का कोई बाजार नहीं है।

   जिस व्यवस्था में दोनों भूमिका (i और ii) की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को मिलती है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते है। इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है लेकिन वह नियामक के तौर पर अपनी भूमिका जरूर निभाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक भूमिका (iv भूमिका) तय होती है, इसमें जरूरतमंद लोगों को जरूरत का सामान मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। कुछ मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में सरकारें ये जिम्मेदारी उठाती हैं या फिर बहुत ज्यादा भार अनुदान देकर वहन करती हैं।

   विश्व बैंक की रिपोर्ट 1999 एक तरह से अर्थव्यवस्था में सरकार की उपयुक्त भूमिका को दर्शाती है। इसके मुताबिक समाजिक और राजनीतिक जरूरत के मुताबिक सरकार की भूमिका में भी बदलाव संभव है।

राजनीतिक समस्याएँ तीन चीजों के मिलने से बनती हैं:

1. आर्थिक निपुणता,
2. सामाजिक न्याय, और
3. व्यक्तिगत स्वतंत्रता।

   इन तीन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में ये इजाजत नहीं दी जा सकती है, कि जिसमें केवल राज्य की भूमिका हो या फिर केवल बाजार की भूमिका हो इन चुनौतियों का सामना तभी हो सकता है जब सरकार और बाजार दोनों को संतुलित भूमिका दी जाए संतुलन की परिभाषा मौजूदा स्थिति और भविष्य के लक्ष्य के आधार पर तय होती है। मौजूदा भूमंडलीकरण की दुनिया में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सटीक संतुलन को ही आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कहते हैं।

अगर हम किसी अर्थव्यवस्था की जरूरत का आंकलन करेंगे तो इसमें राज्य की कुछ अनिवार्य भूमिका नजर आएगी:

1. अगर किसी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति या फिर समूह पर नियमन और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो वह दूसरों की कीमत पर खुद मुनाफा कमाने पर जोर देंगे। ऐसे में ये भूमिका सरकार के अधीन ही होनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त भी है क्योंकि इससे बड़ी आबादी के हितों का ख्याल रखना संभव है।
2. सामान का उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंपी जा सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र मुनाफा कमाने वाला क्षेत्र है। सरकार अगर इस क्षेत्र की जिम्मेदारी उठाती है तो उस पर काफी बोझ पड़ेगा। हालांकि दुनिया के कई देशों में उपयुक्त निजी क्षेत्र की मौजूदगी नहीं होने से यह जिम्मेदारी सरकारों के अधीन भी है। भारत भी उन देशों में एक है। हालांकि कुछ देशों में निजी क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए सरकारों ने यह जिम्मेदारी पूरी तरह से निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ा हुआ है। भारत में यह प्रक्रिया विलंबित है जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया में सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है, ताकि निजी क्षेत्र आ सकें।

3. हालांकि जरूरतमंद लोगों के लिए रोजमर्रा के जीवन में जरूरी उत्पादों की आपूर्ति निजी क्षेत्र पर नहीं छोड़ी जा सकती है क्योंकि यह नुकसान देने वाला है। इसका मतलब यह है कि सरकार को यह जिम्मेदारी खुद लेनी होगी या फिर अपनी जिम्मेदारी को इस क्षेत्र में बढ़ाना होगा भारत में आर्थिक सुधारों के बाद यही स्थिति है निजी क्षेत्र सामानों के उत्पादन और वितरण में सक्षम है, लिहाजा सरकार इस क्षेत्र विशेष में लगे अपने मानव और आर्थिक संसाधनों की बचत कर सकती है।
विश्व बैंक के अध्ययन के मुताबिक, पूर्वी एशियाई चमत्कार (1993) में यह देखा गया कि ऊपर के उदाहरण से एक तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था दूसरी तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई। यह बदलाव मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था में नजर आया, यहाँ यह बदलाव 1960 के दशक से हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में यह बदलाव उपयुक्त समय पर शुरू नहीं हुआ। 1991-92 में यह काफी देरी से शुरू हुआ और इसे अनिवार्य किया गया। पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में भी इसी तरह के सुधार हुए लेकिन वे अपनी मर्जी से किए गए थे।

पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र- बदलते आर्थिक परिदृश्य एवं भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र (Vision Documents) लागू करने का निर्णय लिया है।

- प्रथम 15 वर्षीय दृष्टिपत्र, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद लागू होगा जो वर्ष 2017-18 से वर्ष 2031-32 तक के लिए होगा।
- इसके अंतर्गत सर्वप्रथम एक 7 वर्षीय राष्ट्रीय विकास एजेंडा लागू किया जाएगा, जिसमें गरीबी उन्मूलन के मूल उद्देश्य के साथ दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों एवं रणनीतियों का निर्धारण किया जाएगा।
- 15 वर्षीय दृष्टि-पत्र में पहली बार रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा (Defence and internal Security) को भी शामिल किया जाएगा। जो कि पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल नहीं किए जाते थे।

नीति आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम

नीति आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के माध्यम से कार्य-स्थल (ऑन-ग्राउंड) पर प्रत्यक्ष नीतिगत हस्तक्षेप भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर,

1. **अटल नवप्रवर्तन मिशन**

- अटल नव प्रवर्तन मिशन - 27 मार्च 2018
- देशभर में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना के लिए 1500 और स्कूलों का चयन किया गया।
- अटल नवप्रवर्तन मिशन नीति आयोग का एक अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देशभर के विद्यालयों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं और अटल इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना है।
- अटल महाचुनौती तथा टिंकरिंग मैराथन के आयोजनों से देशभर के युवा उद्यमियों को सीखने, कुछ नया अविष्कार करने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से जुड़ने के लिये प्रोत्साहन मिला है।
- अभी तक 2441 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला विद्यालयों का चयन किया जा चुका है।
- प्रत्येक अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना लागत के तौर पर 10 लाख रुपए की एकमुश्त राशि और अधिकतम 5 वर्षों के लिये 10 लाख रुपए के प्रचालन व्यय सहित अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है।
- वर्तमान में देश के सभी राज्यों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ मौजूद हैं।

2. **सहयोगपूर्ण संघवाद-** सहकारी संघवाद में केन्द्र व राज्य एक-दूसरे के साथ **क्षैतिज** संबंध स्थापित करते हुए एक-दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं।
- संघ और राज्य संवैधानिक रूप से संविधान की 7 वीं अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों पर एक-दूसरे के साथ सहयोग करने हेतु बाध्य है।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन करना।
- कौशल विकास को प्रोत्साहन देना।
- स्वच्छ भारत को प्रोत्साहन देना।
- डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देना।
- आकांक्षी जिलों में बदलाव के कार्यक्रम के लिए देशभर के 115 जिलों के जिलाधिकारियों तथा प्रभारी अधिकारियों का सहयोग लेना।
- सचिव समूहों द्वारा नीति आयोग को अभ्यावेदन देकर विभिन्न मंत्रालयों के बीच चर्चा और सहयोग करना।

3. **प्रतिस्पर्धी संघवाद-** प्रतिस्पर्द्धी संघवाद में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य संबंध लंबवत होते हैं जबकि राज्य सरकारों के मध्य संबंध क्षैतिज होते हैं।
- यह भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है।
- राज्यों की रैंकिंग के लिए डिजिटल परिवर्तन सूचकांक तथा नवप्रवर्तन सूचकांक की शुरुआत करना।

नीति आयोग द्वारा की गयी पहलः

इसकी महत्त्वपूर्ण पहलों में "15 साल का रोड़ मैप", "7 साल का विज़न, रणनीति और कार्य योजना", AMRUT, डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन शामिल हैं।

नीति आयोग और योजना आयोग में प्रमुख अन्तर

नीति आयोग	योजना आयोग
यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।	इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था।
यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है।	यह सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था।
यह Bottom - up - Approach पर कार्य करता है।	यह Top - Down Approach पर कार्य करता था।
इसे धन आवंटित करने की शक्तियाँ नहीं है जो वित्त मंत्री में निहित है ।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियाँ प्राप्त थीं ।

सरकार की पहलें

1. कीन्स का सिद्धांत

- कीन्स का सिद्धांत या कीन्स का रोजगार सिद्धांत मंदी अथवा अवसाद की स्थिति में रोजगार से संबंधित है।
- जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट में किया था।
- कीन्स के अनुसार मंदी या अवसाद की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समग्र माँग या समग्र व्यय की कमी के कारण होती है।
- इस प्रकार समग्र व्यय की वृद्धि के द्वारा बेरोजगारी में कमी लायी जा सकती है।
- अर्थव्यवस्था में व्यय की वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था की अवसाद से बाहर निकालने के लिए कीन्स पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सरकारी व्यय पर बल दिया।
- कीज का विश्लेषण मुख्यतः अल्पकालिक विश्लेषण था ।

2. हैरोड-डोमर मॉडल

हैरोड-डोमर मॉडल आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निवेश को एक महत्वपूर्ण तत्व मानते है क्योंकि निवेश दोहरी भूमिका निभाता है।

- एक ओर तो आय का निर्माण होता है और वहीं दूसरी ओर पूंजी स्टॉक में वृद्धि करके देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है।
- निवेश की इस पहली विशेषता को 'मांग प्रभाव' और दूसरी को 'पूर्ति प्रभाव' कहा जाता है।

3-नेहरू-महालनोबिस मॉडल

- सैद्धांतिक अर्थशास्त्र भाग में बहुत अधिक जाए बिना, मॉडल निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है ।
- औद्योगिक विकास के निम्नतम स्तर पर एक देश के लिए, सबसे पहले भारी उद्योगों को प्रधानता दी जानी चाहिए ।
- (पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता के निर्माण के लिए)
- जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, हम कैपिटल इक्विटी और सेवाओं का आयात नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए काफी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ।
- भारत के पास आयात करने के लिए निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं नहीं हैं ।
- भारी उद्योगों की स्थापना लंबे समय में औद्योगीकरण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में है
- इस तरह के मॉडल एक विफलता नहीं थी।
- भारत ने औद्योगीकरण के लिए एक ठोस आधार बनाया ।
- भारत ने नई तकनीकों को अवशोषित करने, धारा उद्योगों को विकसित करने की क्षमता में काफी लाभ हासिल किया ।
- संसाधनों के प्रसार के साथ, परियोजनाओं को उत्पादन शुरू करने में बहुत समय लगा ।
- कई परियोजनाओं ने रोजगार सृजन के नाम पर बहुत अधिक मैन पावर लिया था।
- लघु /मध्यम उद्योग पूरी तरह से उपभोक्ता क्षेत्र की सेवा नहीं कर सके और लाइसेंस / आरक्षण प्रणाली ने कमी / प्रतीक्षा समय का निर्माण किया।

भारत में पंचवर्षीय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56 ई.)

- यह योजना हैरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी।
- इस योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र पर थी।
- इस योजना में भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुण्ड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत की गई।
- इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (Community Training Programme) (1952) तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा

- इसमें गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया।
- इस योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- जनसंख्या में वृद्धि पर नियंत्रण के लिए विविध नीतियों को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से सम्बंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, TRYSEM, DWACRA, RLEGP लागू किये गये।
- ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी निवारण से सम्बन्धित कई योजनाएँ चलाई गयी।
- ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना की गयी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90 ई.)

- इस योजना में भारी तथा पूँजी प्रधान उद्योगों के स्थान पर कृषि, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास पर बल दिया गया।
- इस योजना में गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के प्रयास किये गये।
- इस योजना के अन्तर्गत, इन्दिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना आदि योजनाएँ लागू की गई।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य, खाद्यान्न एवं उत्पादकता में वृद्धि करना था।
- "गरीबी की माप" सबसे पहले इसी योजना में लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी।

वार्षिक योजनाएँ (Annual Plans)
(1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1992 तक)

- 7वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद राजनैतिक अस्थायित्व और भुगतान संतुलन संकट के कारण सरकारों के जल्दी-जल्दी बदलने से 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ नहीं हो सकी।
- वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक सुधार (उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण (LPG)) की घोषणा की गई।
- 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992) में महालनोबिस मॉडल के स्थान पर राव मनमोहन मॉडल को स्वीकार किया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97 ई.)

- यह योजना जॉन डब्ल्यू. मूलर मॉडल पर आधारित थी।
- इस योजना का उद्देश्य, मानव संसाधन विकास (Human Resource Development) था।
- मैला ढोने की कुप्रथा को पूर्णतः समाप्त करना।
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई ।
- आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही LPG Reform (Liberalisation, Privatisation and Globalisation) आये गये थे।

नौवीं योजना (1997-2002 पंचवर्षीय ई.)

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना था।
- इस योजना में स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा को सुनिश्चित करना आदि था।
- इस योजना में पंचायती राज संस्थाओं, सहकारिताओं तथा । स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07 ई.)

- दसवीं योजना व्यापक आगत-निर्गत मॉडल (Extensive Input- output Model) पर आधारित थी।
- इस योजना में सर्वाधिक बल कृषि विकास पर था, जबकि ऊर्जा पर सर्वाधिक व्यय किया गया।
- इस योजना के प्रारंभिक वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी।

ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012 ई.)

इस योजना का उद्देश्य, अधिक तीव्र और ज्यादा समावेशी संवृद्धि (Faster and More Inclusive Growth) था।

ग्यारहवीं योजना के मुख्य तत्व :

- तेज आर्थिक संवृद्धि (9% प्रतिवर्ष जिसे संशोधित कर 8.1% कर दिया गया) जो गरीबी को कम कर सके तथा रोजगार के अवसर बढ़ा सके।
- स्वास्थ्य तथा शिक्षा में सेवाओं की वृद्धि।
- विकास में सभी को समान अवसर देना।
- शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक बल।
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
- पर्यावरण सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया।
- लैंगिक समानता पर बल।
- साक्षरता दर को कम से कम 75% के स्तर तक पहुँचाना।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17 ई.)

- गैर कृषि क्षेत्र 50मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना ।
- 0-3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना ।
- वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना ।
- ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना ।
- हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना ।
- देश के 90%परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना ।

योजना	वृद्धि दर का लक्ष्य	औसत वृद्धि दर	मॉडल	मुख्य उद्देश्य
प्रथम (1956-61)	2.1	3.6	हेरॉल्ड-डोमर मॉडल	कृषि विकास पर बल, उत्पादन आय तथा धन का समान वितरण
द्वितीय (1956-61)	4.5	4.2	नेहरू-महालनोबिस	औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, आधारभूत एवं भारी उद्योग का विकास
तृतीय (1961-66)	5.6	2.7	जे सैंडी, सुखमोय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल	रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, इस योजना के बीच में भारत का चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध हुआ।
चतुर्थ (1969-74)	5.7	2.2	डी.आर. गॉडगिल	समाज में समानता स्थापित करना, स्थिरता के साथ आत्म-निर्भरता
पाँचवीं (1974-78)	4.4	4.8	डी. पी.धर मॉडल	गरीबी उन्मूलन तथा आत्म-निर्भरता
छठी (1980-85)	5.2	5.2	आगत निर्गत	निर्धनता का उन्मूलन करना, गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन
सातवी (1985-90)	5.0	5.8	जान डब्ल्यू मिलर	रोजगार के नये अवसरों को पैदा करना, कृषि विकास प्रेरित समृद्धि की रणनीति।
आठवी (1992-97)	5.6	6.6		प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापि बनाना, मानव संसाधन का विकास
नौवी (1997-2002)	6.5	5.5	आगत-निर्गत	समाजिक न्याय तथा समता के साथ विकास
दसवीं (2002-07)	7.9	7.5	व्यापक आगत निर्गत माडल	समावेषी संवृद्धि के साथ विकास
ग्याहरवीं (2007-12)	8.1	7.9	योजना आयोग का विकास	तीव्र व समावेशी विकास
बारहवीं (2012-17)	8.0	7.1		त्वरित समावेषी विकास

पंचवर्षीय योजनाओं का अवलोकन –

भारतीय पंचवर्षीय योजना				
पंचवर्षीय योजना	vof/k	प्राथमिक क्षेत्र	लक्ष्य की दर	वृद्धि दर
पहली योजना	1951-56	कृषि, बिजली, सिंचाई	2.1	3.6
दूसरी योजना	1956-61	पूर्ण उद्योग	4.5	4.2
तीसरी योजना	1961-66	उद्योग	5.6	2.8
चौथी योजना	1969.74	कृषि	5.7	3.2
पाँचवें योजना	1974-79	गरीवी उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता	4.4	5
छठी योजना	1980-85	कृषि, उद्योग	5.2	5.5
सातवीं योजना	1985.90	ऊर्जा, [kk|	5	6
आठवीं योजना	1992-97	मानव स्रोत, शिक्षा	5.6	6.6
नौवीं योजना	1997-02	सामाजिक न्याय	6.5	5.4
दसवीं योजना	2002-07	रोजगार, ऊर्जा	8.1	7.6
ग्यारहवीं योजना	2007-12	समावेशी विकास	8	7.9
बारहवीं योजना	2012-17	त्वरित	8	8

अध्याय - 6

वित्तीय संस्थाएं (बैंकिंग)

- बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता की धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है।
- लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार समय-समय पर निकालते रहते हैं।
- बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं।

भारत में बैंकिंग

- भारत में स्थापित पहली बैंक Bank of Hindustan थी इसकी स्थापना Alexandey and Company 1770ई. में की थी कुछ समय बाद यह बैंक बन्द हो गई।
- इसके बाद देश में निजी और सरकारी अंशधारियों द्वारा तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों की स्थापना की गई - वर्ष 1806 में बैंक ऑफ बंगाल (Bank of Bengal.), वर्ष 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे (Bank of Bombay) तथा वर्ष 1843 में बैंक ऑफ मद्रास (Bank of Madras) ।
- इन तीनों बैंकों पर बैंक ऑफ मद्रास अपना नियंत्रण रखती थी । बाद में इन बैंकों के कार्यों को सीमित कर दिया गया । वर्ष 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया (Impe rial Bank of India) की स्थापना की गई और । जुलाई, 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया ।
- भारत में पहली सीमित देयता वाला भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था जिसकी स्थापना फैजाबाद में वर्ष 1881 में की गयी थी ।
- उसके बाद वर्ष 1894 में लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई जो पहला पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक था ।

भारत में स्थापित प्रमुख बैंक व उनकी स्थापना

बैंक का नाम	स्थापना वर्ष
द बैंक ऑफ हिन्दुस्तान	1770
बैंक ऑफ बंगाल	1806
बैंक ऑफ बॉम्बे	1840
बैंक ऑफ मुद्रास	1843
इलाहाबाद बैंक	1865
एलाइन्स बैंक ऑफ शिमला	1881
अवध कॉमर्शियल बैंक	1881
पंजाब नेशन बैंक	1894
बैंक ऑफ इंडिया	1906
पंजाब एंड सिंध बैंक	1908
बैंक ऑफ बडौदा	1909
सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1911
बैंक ऑफ मैसूर	1913
इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया	1921
भारतीय रिजर्व बैंक	1935
भारतीय स्टेट बैंक	1955

भारतीय रिजर्व बैंक

- भारत का केन्द्रीय बैंक है ।
- वर्ष 1930 में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (R.B.I.) की स्थापना RBI अधिनियम, 1934 के तहत् । अप्रैल, 1935 को 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से हुई थी ।
- । जनवरी, 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । इसके प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ (1935-37) थे ।
- देश के स्वतंत्रता के समय में RBI के गर्वनर सर सी डी देशमुख (1943-49) थे ।
- रिजर्व बैंक के कार्यों का संचालन केन्द्रीय संचालक मण्डल (Central Borad of Directors) द्वारा होता है ।
- सम्पूर्ण देश में इसे चार भागों में बाँटा गया है - उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र ।
- इसमें प्रत्येक के लिए 5 सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड (Local board) होता है ।
- केन्द्रीय बोर्ड में । गवर्नर तथा अधिक से अधिक 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार पाँच वर्षों के लिए करती है ।
- वर्तमान में RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास (12 दिसम्बर, 2018 से लगातार)है।
- स्थानीय बोर्डों के कार्यालय नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुम्बई में हैं ।
- स्थानीय बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड के आदेशानुसार कार्य करते हैं।
- रिजर्व बैंक का प्रधान अथवा केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में स्थित है ।
- नई दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई में स्थानीय प्रधान कार्यालय है

RBI के कार्य

भारत में नए नोट जारी करने की व्यवस्था

- एक रुपये के नोट का सभी सिक्कों को छोड़कर रिजर्व बैंक को विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करने का एकाधिकारक प्राप्त है ।
- रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक रुपए के नोटों तथा सिक्कों एवं छोटे सिक्कों का देशे में वितरण का कार्य करता है ।
- करेन्सी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति (Minimum Reserve System) को अपनाता है । इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋणपत्र कुल मिलाकर

किसी भी समय 200 करोड़ रुपये के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए । इनमें स्वर्ण का मूल्य (धातु तथा मुद्रा मिलाकर) 115 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। यह पद्धति रिजर्व बैंक ने 1957 के बाद अपनाई थी ।

- **NOTE**–नए नोट छापने की एक अन्य व्यवस्था भी है परन्तु इसका प्रयोग भारत में नहीं होता यह व्यवस्था अनुपाती आरसी व्यवस्था है (Prahetional Resere system) इसके अन्तर्गत जिस अनुपात में नए नोट का मूल्य बढ़ता है उसी अनुपात में रखे गए कोष को बढाना पड़ता है
- **NOTE** – 1000 रुपये के नोटों का परिचालन 8 नवम्बर, 2016 से बंद हो गया है।

NOTE– सिक्के सीमित विधि ग्राह्य (Limited Legal Tender) हैं । भारत में कागजी नोट असीमित विधि ग्राह्य(Unlimited Le gal Tender) हैं । इसका अर्थ यह है कि भुगतान का निपटारा करने के लिए सिक्कों का प्रयोग केवल एक सीमा तक ही किया जा सकता है । इसके विपरीत, कागजी नोटों के रूप में भुगतानों का निपटारा करने हेतु उनका प्रयोग असीमित मात्रा में किया जा सकता है ।

सिक्कों का उत्पादन

- सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चाँदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की पाँच टकसालें मुम्बई, अलीपुर (कोलकाता), सैफाबाद (हैदराबाद), चेर्लापल्ली (हैराबाद) तथा नोएडा में स्थित है ।
- टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों (मेडल) का भी उत्पादन किया जाता है ।
- **NOTE**– 25 पैसे तथा इससे कम मूल्य के सभी सिक्कों का परिचालन जुलाई, 2011 से बंद हो गया है । अर्थात देश में अब 50 पैसे का सिक्का सबसे कम मूल्य की विधिग्राह्य मुद्रा है ।

1. **इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस,नासिक (महाराष्ट्र)** –

- भारत प्रतिभूति में डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक - भिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर - अदालती स्टाम्पों, बैंकों (RBI तथा SBI) के चेकों, बॉण्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है ।

2. **सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस, हैदराबाद**

- सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने के लिए की गई तथा यहाँ पूरे देश की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की छपाई भी होती है।

3. **करेन्सी नोट प्रेस, नासिक (महाराष्ट)**

- नोट प्रेस 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 तथा 2000 रुपये के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है ।

4. **बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश)**

- देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपये के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है ।
- बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण करता है ।

5. **साल्बोनी (पं . बंगाल) तथा मैसूर (कर्नाटक) के भारतीय रिजर्व बैंक ने दो नयी एवं अत्याधुनिक करेन्सी नोट प्रेस स्थापित की गयी है । यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में करेन्सी नोट छापे जाते हैं।**

6. **सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)**

बैंक और करेन्सी नोट कागज तथा गैर - ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 1967-68 में चालू की गई थी ।

सरकार के बैंकर का कार्य करना

- सरकारी बैंकर के रूप में यह निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करता है-

1. भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से धन प्राप्त करना और इनके आदेशानुसार इनका भुगतान करना ।
2. भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से जनता से ऋण प्राप्त करना ।
3. सरकारी कोषों का स्थानान्तरण करना ।
4. भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए विदेशी विनिमय का प्रबन्ध करना ।
5. भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को आर्थिक सलाह देना।

रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक

- बैंकों के बैंक के रूप में यह निम्नलिखित कार्य करता है

1. रिजर्व बैंक व्यापरिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है ।
2. रिजर्व बैंक बैंकों की साख नीति का नियंत्रण रखता है ।
3. वर्ष 1949 के बैंकिंग नियमन अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार प्राप्त है ; जैसे - अनुसूचित बैंक का निरीक्षण करना, नए बैंकों की स्थापना के लिए अनुज्ञा - पत्र प्रदान करना, आदि।

विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण करना

- केन्द्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय कोष के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है । केन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं के कोष संचित रखता है जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विकास तथा विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखा जा सके।

कृषि साख की व्यवस्था करना

- कृषि साख की व्यवस्था करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक कृषि साख विभाग की स्थापना की है । इस विभाग का मुख्य कार्य कृषि साख से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना है ।

पूंजी है जो की एक कम्पनी का संस्थापक एवम् अन्य शेष धारक उस कंपनी की स्थापना में निवेश करते है

3. उन बैंकों को RBI द्वारा जारी मौद्रिक नीतियों का अनुपालन करना होता है आवश्यकता पड़ने पर यह बैंक RBI से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते है

- विश्व की सबसे बड़ी Bank. I.P Mangon Chese है यह एक अमेरीकी बैंक है परन्तु भारत में यह बैंकिंक सेवाएँ नही प्रदान करती भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों में सबसे बड़ी बैंक HSBC है जिसका मुख्यालय लंदन में है
- भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों में सर्वाधिक शाखाएँ stancdland chailed बैंक की है यह भी एक Boilish Bank है।
- कुल परिसंपत्ति के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी बैंक JCBC है
- बाजारी पूंजीकरण के आधार पर भारत की सबसे बड़ी बैंक HDFC Bank है परन्तु शाखाओं के आधार पर लाभ के आधार पर एवम् के आधार पर SBI भारत की सबसे बड़ी बैंक है।
- परिसंपत्ति के आधार पर SBI भारत की सबसे बड़ी बैंक है।
- Rupco Bank जो की एक सहकारी Bank है, भारत की एक मात्र ऐसी बैंक है जो गृहमंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत है।

भुगतान बैंक (Payments Bank)

- बैंकिंग सेवाओं में विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त, 2015 को भुगतान बैंकों को सैद्धान्तिक मंजूरी दी।
- वर्ष 2014-15 के आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विशिष्ट प्रकार के बैंक की बात की थी जो क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय लोगों के निजी हितों का ध्यान रखते हुए बैंकिंग करेंगे।
- **भुगतान बैंकों की विशेषताएँ हैं-**

1. खाताधारक ₹ 1 लाख तक की धनराशि जमा कर सकेंगे।
2. ATM डेबिट कार्ड जारी कर सकेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड कर सकेंगे।
3. पैसों का लेन - देन किया जा सकेगा ऋण नहीं दे सकेंगे।
4. केवल नकदी व सरकारी प्रतिभूतियाँ ही जमा कर सकेंगे।

- वाणिज्यिक बैंकों की तरह यह भी CRR के रूप में 4% की राशि रखेंगे
- कुल जमा राशि का कम से कम 75% हिस्सा SLR के रूप में रखनी होगी जो कि सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में होगी।
- अतिरिक्त आय के लिए यह बैंक बीमा कम्पनियों के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं बेंच सकती है साथ ही Mutual fund योजनाएं भी बेच सकती है।
- वर्ष 2013 में RBI ने पेमेण्ट बैंक (भुगतान बैंक) के लिए पेपर जारी किया था।
- इसके बाद नचिकेत मोर कमेटी गठित कर RBI ने 11 कम्पनियों को पेमेण्ट बैंक के लाइसेन्स इनमें शामिल हैं- एयरटेल, वोडाफोन, आदित्य बिरला ग्रुप मण्डलम, टेक महिन्द्रा रिलायन्स तथा भारतीय डाक विभाग।
- जिन मोबाइल टेलीफोन कम्पनियों और सुपर बाजार श्रृंखला के स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीयों के पास है वे भुगतान बैंक से हो सकते हैं।
- भुगतान बैंक के लिए इक्विटी कैपिटल की सीमा न्यूनतम होनी चाहिए। इसका प्रसार क्षेत्र पूरे भारत में हो सकता है।

लघु वित्त बैंक

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने छोटे किसानों और कुटीर उद्योगों को बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए 16 सितम्बर, 2015 को 10 कम्पनियों को लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक मजूरी दी।
- लघु वित्त बैंक छोटे किसानों कुटीर उद्योग, लघु और अतिलघु एवं असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को प्राथमिक बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करवाएँगे।
- इन बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में कम - से - कम 50 % योगदान ₹ 25 लाख तक के ऋण और अग्रिमों का होना अपरिहार्य है।

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेन्स एजेंसी (मुद्रा) बैंक

- माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाईनेन्स एजेन्सी (मुद्रा) बैंक 2015 के बजट में की गई है जिसके लिए ₹ 20,000 करोड़ निर्धारित किया गया है और इसमें ₹ 3,000 करोड़ की ऋण राशि की घोषणा की गई है।
- मुद्रा बैंक **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** के जरिए सूक्ष्म वित्त संस्थान पुनर्वित्तीयन करेगा तथा कर्ज देते समय अनुसूचित जाति / जनजाति को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ₹ 50 हजार से ₹ 10 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत तीन तरह के ऋण दिए जाते है

1. शिशु ऋण- ₹ 50.000 तक के ऋण हेतु
2. किशोर ऋण- ₹ 50,000 से अधिक तथा ₹ 5 लाख तक
3. तरुण ऋण- ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक

भारतीय महिला बैंक लिमिटेड

- उद्घाटन-19 सितंबर, 2013
- प्रारंभिक पूँजी- 1000 करोड़
- स्थापना - मुम्बई मुख्यालय- नई दिल्ली
- स्वरूप- समाज में महिलाओं को समान अवसर देने और उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारतमें प्रथम बैंक की नींव रखी।
- उद्देश्य- सभी वर्गों की महिलाओं के लिए वित्तीय सुविधाओं को सुगम बनाना, महिलाओं का सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन। आर्थिक सशक्तीकरण के लिये महिलाओं को आर्थिक संस्थाओं और परिसंपत्तियों पर नियंत्रण की समान सुविधाएँ प्रदान करना।

- पाकिस्तान और तंजानिया के पश्चात् भारत ऐसा तीसरा देश है जिसने महिलाओं के लिए विशेष बैंक स्थापित किया है। 31 मार्च, 2017 को भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया है।

Islamic Bank

- इस्लामिक Bank एक NBFC के रूप में कार्य करती हैं चूंकि यह इस्लामिक नियमों का अनुपालन करती हैं।
- यह ऐसे किसी भी क्रिया से सम्बंध नहीं रखेगी जो की इस्लाम में हराम माना गया हो।
- दुनिया भर में पहला इस्लामिक बैंक मलेशिया में वर्ष 1983 में स्थापित हुआ था।
- भारत में सबसे पहला इस्लामिक बैंक वर्ष 2011 में केरल हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोच्ची (केरल) में स्थापित किया गया जिसका नाम Charraman Financial services Limited हैं।
- वर्ष 2016 में जेद्दा के इस्लामिक डेवेलपमेंट बैंक (IDB) की शाखा गुजरात में खोली गई। यह बैंक प्रधानमंत्री मोदी के क़रीबी ज़फ़र सरेशवाला के नेतृत्व में खोला गया था।
- इस्लामिक बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश 1000 रु. की होनी चाहिए यह NBFC न ब्याज देगी और न ही ब्याज लेगी अतः इस NBFC को प्राप्त राशि जमा राशि के रूप में नहीं बल्कि निवेश के रूप में होगी इस्लामिक बैंक निर्माण, घाटे की भागीदार होगी
- यह शराब से संबंधित अथवा जुआ से धार्मिक आधारों पर बैंकिंक व्यवस्था से नहीं जुड़ पाते ऐसी स्थिति में विनिर्माण एवम् सेवा क्षेत्र में पूंजी प्रदान करेंगे परन्तु यह पूंजी ऋण के रूप में न होकर निवेश के रूप में होगी अतः इस्लामिक बैंक लाभ अथवा संबंधित एवम् अन्य ऐसे किसी भी व्यापार में की इस्लाम में हराम हो निवेश नहीं करेगी।
- इस्लामिक बैंक भी वित्तिय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान कर सकती हैं चूंकि इस्लाम का अनुपालन करने वाले भारत के कई परिवार, इस्लामीक बैंक एक विकल्प का कार्य करेगी साथ ही इसके माध्यम से घरों में पड़े अधिशेष राशि को अर्थव्यवस्था में लाया जा सकता हैं

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India- IDBI)

- इसकी स्थापना RBI ने 1964 में की थी परन्तु यह एक गैर बैंकिंक वित्तिय कम्पनी के रूप में (NBFC) कार्यरत थी जो की बड़े उद्योगों के स्थापना के उद्देश्य से ऋण प्रदान करती हैं
- इसका मुख्यालय मुम्बई में हैं।
- लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से 1948 की ती एक ईकाई के रूप में SIDBI (Small Indus tries Development Bank of India) की स्थापना की गयी, इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित हैं। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी परन्तु अधिनियम 1989 में पारित किया गया था
- वर्ष 1976 में IDBI का मालिकाना अधिकार भारत सरकार को दे दिया गया एवम् वर्तमान में IDBI को एक पूर्णतः बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया हैं।

क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank)

- RRB की स्थापना एक क्षेत्र विशेष के ग्रामीण हिस्सों में ही की जाती हैं उनका मुख्य उद्देश्य कृषि के लिए ऋण प्रदान करना एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान करना हैं इनके संस्थापक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही होते हैं इनकी स्थापना में पूंजी निवेश केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवम् राज्य सरकार करती हैं।
- केन्द्र सरकार का योगदान 50%, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक का योगदान 35% एवम् राज्य सरकार का योगदान 15% होता हैं
- भारत में 02 अक्तूबर, 1975 को 4 राज्यों के 5 क्षेत्रों में सर्वप्रथम क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई परन्तु RRB अधिनियम 1976 में पारित हुआ यह 5 क्षेत्र एवम् 4 राज्य निम्नलिखित हैं- उत्तरप्रदेश- मुरादाबाद, गोरखपुर
  हरियाणा- भिवानी
  राजस्थान जयपुर
  प. बंगाल - माल्दा
- वर्ष 1990 के दशक में सुधारों के बाद सरकार ने वर्ष 2005-06 में समेकन कार्यक्रम शुरू किया जिसके परिणामस्वरूप RRB की संख्या वर्ष 2005 में 196 से घटकर वित्त वर्ष 2021 में 43 हो गई और इन 43 RRBs में से 30 ने शुद्ध लाभ प्रदान किये।

Co-operative Bank

- भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किसानों, कारीगरों और समाज के अन्य वर्ग के लोगों के विकास में मदद करने हेतु बचत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई थी।
- भारतीय सहकारी बैंकिंग का इतिहास वर्ष 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के पारित होने के साथ शुरू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य सहकारी ऋण समितियों की स्थापना करना था।
- स्वतंत्रता के बाद पहले 3 वर्षों के दौरान यानी वर्ष 1949 तक सहकारी बैंकिंग की दृष्टि से कुछ भी महत्त्वपूर्ण कार्य संभव नहीं हो पाया।
- हालांकि तब तक तात्कालिक भारतीय नेता देश की जड़ों को मज़बूत करने के लिये सहकारी बैंकों की भूमिका को पहचान चुके थे एवं इसी कारण शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं में देश के सहकारी ढाँचे को मज़बूत करने हेतु अलग-अलग प्रावधान किये गए।
- छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना ने देश के सहकारी ढाँचे के विस्तार और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स" (BIS) में विद्यमान है, इसलिए इन्हें बेसल मानक की संज्ञा दी गई है।

- वर्ष 1974 में G-10 देशों द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स' के तत्वावधान में 'बेसल समिति' का गठन किया गया था। इस समिति ने वर्ष 1988 में ऋण जोखिम के
संबंध में बैंकों के लिए न्यूनतम पूँजी की जरूरत हेतु नियम दिए जिसे 'बेसल-I मानक' कहा जाता है। बेसल-I पूर्णतः ऋण जोखिम (Credit Risk) पर केंद्रित था। जून, 2004 में पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल-II मानकों का निर्धारण किया गया। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को एक निश्चित मात्रा में धनराशि को अपने पास सुरक्षित रखने के मानक तय किए गए थे।

बेसल-III

- इन मानकों को 3 दिसंबर, 2010 को जारी किया गया था और यह बेसल समझौते की श्रृंखला का तीसरा चरण है।
- ये समझौते बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन पहलुओं से जुड़े हैं (बेसल-I और बेसल-II इसके पूर्व संस्करण थे लेकिन कम कठोर थे)।
- ये मानदंड 31 मार्च, 2015 से कई चरणों में लागू हो चुके हैं।
- बेसल-III सुधार उपायों का एक व्यापक सेट है जिसे बेसल समिति ने, बैंकिंग क्षेत्र में विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर तैयार किया है।
- बेसल-III बेसल समिति द्वारा बेसल-I और बेसल-II के तहत बैंकिंग नियामक रूपरेखा में सुधार हेतु बैंकिंग पर्यवेक्षण पर शुरू किए गए प्रयासों का अगला कदम है। यह नवीनतम समझौता वित्तीय एवं आर्थिक तनाव से निपटने में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता और जोखिम प्रबंधन में सुधार एवं बैंक की पारदर्शिता को मजबूत बनाना चाहता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती है और जिसका प्रमुख कार्य उधार देना तथा विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार तथा चिटफंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना होता है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं।
- यह संस्थाओं का विजातीय समूह है (वाणिज्यिक सहकारी बैंकों को छोड़कर) जो विभिन्न तरीकों से वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करता है जैसे – जमा स्वीकार करना, ऋण और अग्रिम देना, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में निधियाँ जुटाना, अंतिम व्ययकर्त्ता को उधार देना, थोक और खुदरा व्यापारियों तथा लघु उद्योगों को अग्रिम ऋण देना।

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में अंतर

बैंक	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
बैंक मांग जमा (Demand Deposits) स्वीकार कर सकते हैं।	NBFC मांग जमा (Demand Deposits) स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली का अंग होते हैं तथा स्वयं द्वारा भुगतेय चेक जारी कर सकते हैं।	NBFC भुगतान और निपटान प्रणाली का अंग नहीं होते हैं तथा स्वयं द्वारा भुगतेय चेक जारी नहीं कर सकते हैं।
बैंकों के जमाकर्त्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) की निक्षेप बीमा सुविधा उपलब्ध होती है।	बैंकों की तरह NBFC के जमाकर्त्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) की निक्षेप बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है।

RBI द्वारा जारी NBFC सम्बन्धी दिशा निर्देश

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र में नए बैंक के प्रवेश सम्बन्धी दिशा - निर्देशों में अच्छे विगत रिकार्ड वाली NBFC को निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर निजी क्षेत्र के बैंक बनने को अनुमति दी गई ।
- NBFC की अद्यतन तुलन - पत्र के अनुसार, कम - से - कम ₹ 200 करोड़ की निवल सम्पत्ति होनी चाहिए, जिसे तीन वर्षों के अंदर ₹ 300 करोड़ तक बढ़ाया जाना होगा ।
- NBFC की किसी बड़े औद्योगिक घराने तथा प्रमोट किया हुआ होना चाहिए अथवा स्थानीय राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार सहित सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्वाधीन / नियन्त्रणाधीन नहीं होना चाहिए। समकक्ष)
- NBFC को पूर्व वर्ष AAA (अथवा रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए । NBFC का भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों / निर्देशों के अनुपालन और सार्वजनिक जमाओं की वापसी अदायगी में विगत रिकार्ड साफ - सुथरा होना चाहिए।

भारत में बैंकिंक क्षेत्र में विदेशी निवेश से सम्बंधित नियम

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए

भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं हो सकती। इन बैंकों में विदेशी निवेश 20% से

मूल्य जबकि आंतरिक मूल्य से आशय धातु के निहित मूल्य से होता है। पहले सोने-चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं का चलन मुद्रा के रूप में था, जबकि वर्तमान में गिल्ट, तांबा आदि धातुओं का प्रयोग धातु मुद्रा में किया जाता है। धातु मुद्रा को सिक्का भी कहते हैं।

कागजी मुद्रा (Paper money)

कागजी मुद्रा एक विशेष किस्म के कागज पर लिखित प्रतिज्ञा पत्र है [मैं धारक को..... (जितने मूल्य का नोट है) अदा करने का वचन देता हूं] है जिसके माध्यम से निर्गमन अधिकारी (केंद्रीय बैंक या सरकार) धारक को उस पर अंकित राशि देने का वचन देता है। इसका निर्गमन एक निश्चित विधान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें केवल बाह्य मूल्य होता है, आंतरिक मूल्य बहुत कम होता है।

भारत की राष्ट्रीय मुद्रा

- भारतीय रुपया (प्रतीक चिह्न ₹ कोड : INR) भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है ।
- इसका बाजार नियामक और जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है ।
- भारतीय मुद्रा के लिए एक अधिकारिक प्रतीक चिह्न जुलाई, 2010 में चुना गया था जिसे IIT गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डी. उदय कुमार ने डिजाइन किया था।
- अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय संघ के यूरो के बाद रुपया पाँचवी ऐसी मुद्रा है, जिसे उसके प्रतीक चिह्न से पहचाना जाता है ।
- रुपया शब्द का उद्गम संस्कृत के शब्द रुप् या रुप्याह् में निहित है जिसका अर्थ चाँदी होता है और रूप्यकम् का अर्थ चाँदी का सिक्का है ।
- रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासनकाल के दौरान किया था।
- शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया वह एक चाँदी का सिक्का था जिसका भार 178 ग्रेन (11.7387 ग्राम) के लगभग था।
- शेरशाह के शासनकाल में भी प्रचलन में रहा ।
- पहले 1 रुपया (1166 ग्राम) 16 आने (या 64 पैसे या 192 पाई) में बाँटा जाता था । यानी 1 आना 4 पैसों या 12 पाई में विभाजित था । 1957 में रुपये का दशमलवीकरण हुआ । इस प्रकार भारतीय रुपया 100 पैसे में विभाजित हो गया । भारत में पैसे को पहले नया पैसा नाम से जाना जाता था ।

नोट

- वर्ष 2011 में नोटों पर रुपये के नए चिह्न का प्रयोग प्रारम्भ हुआ ।
- भारतीय नोट पर उसकी कीमत 15 भाषाओं में लिखी जाती है ।
- रुपया भारत के अलावा इंडोनेशिया, मॉरीशस, नेपाल,पाकिस्तान और श्रीलंका की भी अधिकारिक मुद्रा है । रुपये को फिएट करेंसी कहते है ।
- ऐसा नहीं कि भारतीय रिजर्व बैंक जितनी मर्जी चाहे उतनी कीमत के नोट छा सकता है, बल्कि वह सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकता है । अगर इससे ज्यादा कीमत के नोट छापने हैं, तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 में बदलाव करना होगा । इसी प्रकार रिजर्व बैंक अधिकतम 1,000 रुपए मूल्यवर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है

नोटों का विमुद्रीकरण

- जब किसी देश की सरकार किसी पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है, तो इसे विमुद्रीकरण (Demonetization) कहते हैं ।
- विमुद्रीकरण के बाद उस मुद्रा की कुछ कीमत नहीं कर जाती ।
- उससे किसी तरह की खरीद - फरोख्त नहीं की जा सकती ।

  सरकार द्वारा बंद किए गए नोटों को बैंकों में बदलकर उनकी जगह नए नोट लेने के लिए समय सीमा तय कर देती है । उस दौरान जिसने अपने नोट बैंकों में जाकर नहीं बदले या जमा नहीं किए उनके नोट कागज का टुकड़ा बनकर रह जाते हैं ।
- सरकार ऐसा कई कारणों से कर सकती है –

  सरकार पुराने नोटों की जगह नए नोट लाने पर पुराने नोटों का विमुद्रीकरणका कर देती है। मुद्रा की जमाखोरी (कालाधन) को खत्म करने के लिए भी बड़े राशि के नोटों का विमुद्रीकरण किया जाता है । आतंकवाद अपराध और तस्करी जैसे आपराधिक कार्यों में भी बड़े पैमाने पर नगद लेन - देन होता है । इन कामों में लिप्त लोग कई बार नगद राशि अपने पास जमा रखते हैं । बाजार में कई बार नकली नोट भी प्रचलन में आ जाते हैं । सरकार नकली नोटों से छुटकारा पाने के लिए पुराने नोट बदल देती है । जालसाजी से बचने के लिए नई तकनीकी से तैयार किए गए ज्यादा सुरक्षित नोट लाने पर भी सरकार पुराने नोटों का विमुद्रीकरण कर देती है । टैक्स चोरी के लिए किए जाने वाले नगद लेन - देन को हतोत्साहित करने के लिए भी सरकारें कई बार विमुद्रीकरण का रास्ता अपनाती हैं **NOTE-** सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण जनवरी, 1946 में किया गया जब 1,000 और 10,000 रुपये के नोटों को वापस ले लिया गया । 1,000, 5,000 और 10,000 रुपये के नए नोट 1954 में पुन शुरू किए गए ।

  वर्ष 1970 के दशक में प्रत्यक्ष कर की जाँच से जुड़ी वानचू समिति ने कालाधान बाहर लाने और उसे खत्म करने के लिए विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था । लेकिन इस सुझाव के सार्वजनिक हो जाने की वजह से कालाधन रखने वालों ने तत्काल अपने पैसे इधर - उधर निकाल दिए ।

• अंतरिम बजट 2024

क्या होता है 'बजट' शब्द का मतलब

- बजट शब्द फ्रेंच भाषा के 'Bougette' से आया है जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला ।
- संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय-व्यय का लेखा-जोखा होता है और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश हुआ
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2024 को सरकार का अतरिम बजट 2024 पेश किया है।

अंतरिम बजट - अंतरिम बजट 'चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्योरा होता है अर्थात यह पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है।

अंतरिम बजट 2024 के बड़े ऐलान

- टैक्स के रेट्स किसी भी प्रकार का कोई बढ़लाव नहीं किया गया
- FY25 में 11.1 लाख करोड़ कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) का ऐलान
  स्फटॉप सोलर प्लान के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट हर माह फ्री बिजली मिलेगी

तीन करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी

नौ करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूहों की कामयाबी से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। हमने लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ करने का फैसला किया है। **निर्मला सीतारमण**

- एनर्जी, मिनरल, सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे
- 40 हजार रेल के डब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदलें जाएंगे
- 'UDAN' स्कीम के तहत छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट बनाएं जाएंगे
- 2030 तक 100 लाख करोड़ टन कोल गैसीफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है
- युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस यानी कोष बनाया जाएगा
- अगले 5 सालों में ग्रामीण आवास योजना में गरीबों के लिए 2 करोड़ घर बनाएंगे
- रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी, अब यह GDP का 3.4% होगा। * आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा
- 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
- वित्त वर्ष 2014 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% कर दिया गया है, जो पहले 5.9% था।
- FY25 के लिए राजकोषीय घाटे लक्ष्य 5.1% आंका गया है।
- FY24 का कुल व्यय संशोधित होकर 44.90 लाख करोड़ रुपये हो गया ।
- वित्त वर्ष 24 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपये हैं।
- FY25 में कुल उधारी का लक्ष्य 11.75 लाख करोड़ रुपये FY24 कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपये हैं।
- FY26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने का लक्ष्य।
- FY25 सकल बाजार उधार 14.13 लाख करोड़ रुपये देखा गया।

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया
  वित्त मंत्री लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री हो गयी हैं
  इससे पहले मोरारजी देसाई थें जिन्हें सबसे अधिक 10 बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है

- पिछले साल की तरह यह बजट भी पेपर लेस बजट है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 58 मिनट भाषण दिया
  'यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने है।
  आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चे की योजना को बजट कहते हैं ।
  संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है।

<u>अभ्यास प्रश्न</u>

1. वर्ष - प्रतिवर्ष रिचार्ट का बजट रहा है । घाटे को कम करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन - सी कार्रवाई / कार्रवाइयों की जा सकती है
1. राजस्व में कमी लाना
2. नई कल्याणकारी योजनाएँ आरंभ करना
3. उपदानों (सब्सिडीज) का युक्तीकरण करना
4. उद्योगों का विस्तार करना
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 1
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2, 3 और 4 **(A)**

2. संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन - सा/ से गैर - योजना व्यय के अधीन आता है / आते हैं ?
1. रक्षा व्यय **2. ब्याज अदायगी**
3. वेतन एव पेंशन **4. उपदान**

RRB (16%), सहकारी बैंक (11%), और SFB (5%) हैं (SLBC रिपोर्ट, 2021 और 2022)।

- मध्यप्रदेश में बैंक शाखाओं की कुल संख्या सितंबर 2022 में बढ़कर 8138 हो गई। वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाएं सितंबर 2022 में 5510 थीं।
- सहकारी बैंक शाखाएं 877 (मार्च 2020) से घटकर 851 (सितंबर 2022) हो गई है ।

- **राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि**

वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 (त्वरित) की तुलना में प्रचलित भावों पर 16.43 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 7.06 प्रतिशत की वृद्धि रही है। आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2021-22 (त्वरित) की तुलना में वर्ष 2022-23(अग्रिम) में 7.06 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान है जबकि वर्ष 2021-22 (त्वरित) में वर्ष 2020-21 (प्रावधिक) की तुलना में 10.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।आधार वर्ष (2011-12) के स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 3,15,562 करोड़ रुपये था। जो वर्ष 2021-22 (त्वरित) एवं 2022-23 (अग्रिम) में बढ़कर 6,00,689 करोड़ एवं 6,43,124 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। जो आधार वर्ष से क्रमशः 90.36 एवं 103.80 प्रतिशत अधिक है।राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों पर वर्ष 2022-23 अग्रिम के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 5.24 प्रतिशत, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 5.42 प्रतिशत की एवं 9.99 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित रही है।स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2021-22 (त्वरित) में 61,534 रुपये थी,जो बढ़कर वर्ष 2022-23 (अग्रिम) में रुपये 65,023 हो गई है, जो गतवर्ष की तुलना में 5.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्शातीहै। प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2021-22 में 121594 रुपये से बढ़कर वर्ष2022-23 (अग्रिम) में 1,40,583 हो गई, जो 15.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। स्थिर कीमतों पर, प्रति व्यक्ति शुद्धआय 2011-12 में 38,497 रुपये से बढ़कर 65,023 रुपये हो गया है, जो इस अवधि के दौरान 68.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

राज्य का राजस्व व्यय, व्यय, ऋण एवं राजकोषीय अनुशासन

वित्तीय वर्ष 2004- 05 से लगातार 14 वर्षों तक राजस्व अधिशेष में रहने के बाद, प्रतिकू ल आर्थि क वातावरण के कारण मध्यप्रदेश राज्य में, वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटा हुआ। कोविड-19 के कारण, राजस्व घाटा वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 (पुनरीक्षित अनुमान) में भी जारी रहा। वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्यघरेलू उत्पाद का 4.18 प्रतिशत रहना संभावित है। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.56 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। इसमें 65000.00 करोड़ का पूंजीगत कार्यों के लिए अतिरिक्त ऋण जो भारत सरकार से प्राप्त होने की संभावना है,

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (पु अ)	2022-23 (ब अ)
राजस्व घाटा	(-) 8,814	2800	18,356	5701	3,736
राजकोषीय घाटा	21,616	32,969	49,869	43,287	52,511
प्राथमिक घाटा	8,920	18,753	33,951	23,246	30,344
GSDP के % के रूप में					
राजकोषीय घाटा	2.60	3.51	5.11	4.18	4.56
राजस्व घाटा	(-) 1.06	0.30	1.88	0.55	0.32
राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान का %	8.44	9.63	10.87	11.67	11.36

स्रोत- वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां					
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियां	1,50,391	1,47,643	1,46,376	1,71,697	1,92,179
शुद्ध सार्वजनिक ऋण में परिवर्तन	18,973	23,430	52,413	40,082	51,829
अग्रिमों की वसूली	83.67	59.27	72.77	2,828.75	24.42
नेट पब्लिक अकाउंट	(-) 326	8,579	(-) 1,562	5,871	2,118

	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 (पु.अ.)	वर्ष 2022-23 (ब.अ.)
आकस्मिकता निधि से निवल प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल प्राप्तियां	1,69,122	1,79,712	1,97,299	2,20,479	2,49,151
राजस्व प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों का %)	88.92	82.16	74.19	77.87	78.34
GSDP के % के रूप में राजस्व प्राप्तियां					
राजस्व प्राप्तियां	18.10	15.73	14.99	16.57	16.96
शुद्ध सार्वजनिक ऋण में परिवर्तन	2.28	2.50	5.37	3.87	4.50
अग्रिमों की वसूली	0.01	0.01	0.01	0.27	0.00
नेट पब्लिक अकाउंट	-0.04	0.91	-0.16	0.57	0.18
कुल प्राप्तियां	20.35	19.15	20.21	21.28	21.65

स्रोत- वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन
नोट- पु.अ.- पुनरीक्षित अनुमान
ब.अ.- बजट अनुमान

राजस्व प्राप्तियों की संरचना रुपए करोड़ में

	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	CAGR (%)	वर्ष 2022-23 (ब.अ.)	वृद्धि (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23)
राज्य कर	51,126	55,855	54,484	64,297	7.94	72,859	13.32
केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	57,353	49,486	46,888	58,378	0.59	64,106	9.81
केन्द्रीय अनुदान	28,624	31,925	35,101	36,896	8.83	44,594	20.87

GSDP के % के रूप में राजस्व प्राप्तियों की संरचना

	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 (पु.अ.)	वर्ष 2022-23 (ब.अ.)
राज्य कर	6.15	5.95	5.58	6.21	6.33
केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	6.90	5.27	4.80	5.63	5.57
केन्द्रीय अनुदान	3.44	3.40	3.60	3.56	3.87

कर राजस्व (रुपए करोड़ में)

कर राजस्व	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	CAGR (%)	वर्ष 2022-23 (ब.अ.)	वर्ष (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23)
भूमि राजस्व	383	562	503	767	25.95	1240	61.74
स्टाम्प और पंजीकरण	5,277	5,568	6,816	7,400	11.92	8,200	10.81
राज्य उत्पाद शुल्क	9,542	10,829	9,526	10,340	2.71	13,255	28.19

ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.)- ग्रामीण अधोसंरचना विकास के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल के तहत ग्रामीण अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वर्ष 1995 में नाबार्ड में आर. आई.डी.एफ. की स्थापना की गई। आर.आई.डी.एफ. की स्थापना राज्यों में अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण, जो कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अधूरी थीं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता के कारण, बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के दिशानिर्देशों के अनुसार कृषि को अपना ऋण देने में असमर्थ थे। इसलिए, भारत सरकार ने वर्ष 1995-96 के बजट में ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की स्थापना की घोषणा की, जिसे नाबार्ड द्वारा उस समय सिंचाई क्षेत्र में चल रही ग्रामीण अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रचलित किया गया। इसके बाद, आर.आई.डी.एफ. को नई ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया गया था और इसका दायरा ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करने के लिए व्यापक था। राज्य परियोजना विभाग (एस.पी.डी.) राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को कम लागत वाली निधि सहायता प्रदान करके ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश का समर्थन करने के लिए ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) से ऋण प्रदान करता है।

अध्याय - 7

मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास

- मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है ।
- मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है ईंधन, खनिज, कृषि और जैव विविधता आदि ।
- मध्य प्रदेश देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य भी है राज्य में हीरा उत्पादन 2019 - 20 में 25,603 हजार टन तक पहुँच गया ।
- वर्तमान कीमतों पर, मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2019 - 20 के लिए 9.07 ट्रिलियन रहा । राज्य का GSDP 2015 -16 और 2019 - 20 के बीच 13.78% के CAGR (रुपये के संदर्भ में) में बढ़ा ।
- मध्य प्रदेश का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) लगभग 2019 - 20 में 8.27 ट्रिलियन (USA $ 4117 .32 बिलियन) 2015 - 16 और 2019 - 20 के बीच, राज्य का NSDP लगभग 14.21% CAGR में बढ़ा ।
- मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 109372 रु. है ।
- मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (BPL POPULATION) 31.65% है।
- 2020 - 21 के लिए राजस्व घाटा 17514 करोड़ GSDP का 1.8 % पर लक्षित है ।
- 2020 - 21 के लिए राजकोषीय घाटा 47360 करोड़ रुपये GSDP का 4.9 % पर लक्षित है ।
- 2018 - 19 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 3.5 % थी जबकि देश 5.8 % थी ।
- 2020 - 21 में मध्य प्रदेश में शिक्षा, खेल कला और संस्कृति क्षेत्र (33,408 करोड़ रुपये) की ओर सबसे अधिक आवंटन किया गया है ।
- 2020 - 21 के लिए कुल व्यय 200343 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।
- 2020 - 21 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति 1,36,596 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।
- मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों में प्रचुरता की दृष्टि से राष्ट्र के 8 प्रमुख खनिज राज्यों में से एक है।
- मध्य प्रदेश भारत का चौथा सबसे खनिज समृद्ध देश है (प्रथम तीन - 1. पश्चिम बंगाल 2. झारखंड 3. उड़ीसा ।
- मध्य प्रदेश में प्रति 100000 व्यक्तियों पर उद्योगों की संख्या 5.24 है ।
- मध्य प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2019 - 20 में 24% है ।
- मध्य प्रदेश ने 2019 - 20 में कृषि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में 35%, 24%, और 41% अर्थव्यवस्था में योगदान दिया इन क्षेत्रों में क्रमशः 7.7%, 4.6% और 8.1 % की वृद्धि हुई ।

- मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स (EASE of DOING INDEX) 2020 में चौथे स्थान पर है (1. आंध्र प्रदेश 2. उत्तर प्रदेश 3. तेलंगाना)

राज्य का आर्थिक वर्गीकरण :-

- मध्य प्रदेश के जिलों को औद्योगिक दृष्टि से विकसित तथा पिछड़े जिलों की श्रेणी में बाँटा गया है -
- प्रदेश के 5 जिलों को विकसित जिला माना गया है, जबकि शेष को पिछड़े जिले की श्रेणी में रखा गया है।

1. **औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिले** – भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, तथा कटनी।
2. **पिछड़े जिले (क श्रेणी)** - देवास, होशंगाबाद, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, तरलाम, शहडोल, उज्जैन, विदिशा, सतना, नीमच, हरदा, श्योपुर।
3. **पिछड़े जिले (ब श्रेणी)** – बैतुल, सीहोर
4. **पिछड़े जिले (स श्रेणी)** – बालाघाट, छतरपुर, दमोह, दतिया, धार, गुना, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, शाजापुर, आगरा, मालवा, अलीराजपुर, सिंगरौली, अनुपपुर, निवाड़ी।

- इसके अलावा राज्य में देवास,इंदौर, पीथमपुर, मंडीदीप और मालपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में 280 से अधिक Farmaceutical unit संचालित है।
- मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नोडल एजेंसी (मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) है।
- यह mega ifrastructure परियोजनाओं के समन्वय, सक्रियण, और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का केंद्र बिंदु है।
- मध्य प्रदेश समुंद्री उत्पादों और पेट्रोलियम उत्पादों सहित दो प्रमुख वस्तुओं का निर्यात करता है।
- FY 21 में (नवम्बर 2020 तक) मध्य प्रदेश में कुल दवा निर्माण, जैविक उत्पाद निर्यात का USA $ 947.86 मिलियन का निर्यात किया गया जो कुल निर्यात का 24% था।
- DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE (DIPIIT) के अनुसार अक्टूबर 2019 और सितम्बर 2020 के बीच मध्य प्रदेश में FDI प्रवाह 225.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- 2020 में मध्य प्रदेश में रीवा सौर ऊर्जा परियोजना (NEW 750 M/W SOLAR POWER PLANT) एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था।

मध्यप्रदेश में कृषि

मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर :-

- मध्यप्रदेश में कृषि दर वर्ष 2011 – 12 में 19.85% एवं वर्ष 2012 – 13 में 20.16% थी।
- वर्ष 2013 – 14 में पशुपालन सहित कृषि विकास दर 24.99 % थी, जिसमें केवल कृषि क्षेत्र का विकास दर 22.11% थी।

कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियाँ :-

- मध्यप्रदेश में कृषि से सम्बंधित क्षेत्रों के लिए समग्र योजना तैयार करने और अन्य गतिविधियों हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि कैबिनेट का गठन किया गया है।
- system of rice intensification method (एस.आर. आई. पद्धति)के प्रयोग से धान का बुवाई क्षेत्र बढ़कर 5.58 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिससे धान के उत्पादन में 3570 वृद्धि हुई है।
- मध्यप्रदेश को लगातार पाँच बार कृषि कार्यण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। (2011 से 2016 तक)
- मध्यप्रदेश को यह अवार्ड 2011 – 12 या 2012 – 13 में कुल खाद्यान कि श्रेणी के लिए मिल था।
- mp की 72. 37% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जिसकी आजीविका का प्रधान साधन कृषि है तथा लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।

मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र :-

1. पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश – मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, खंडवा, आदि ज्वार एवं कपास के क्षेत्र है।
2. उत्तर में ज्वार – गेंहू का प्रदेश – मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, छतरपुर, गुना, शिवपुरी, दतिया, तथा टीकमगढ़ का जिला है।
3. मध्य गेंहू का प्रदेश – इसमें भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, नरसिंहपुर, सागर तथा दमोह जिले शामिल है।
4. चावल गेहूँ का प्रदेश - इसमें उत्तर में पन्ना, सतना, कन्नी, उमरिया, जबलपुर, तथा सिवनी के दक्षिण तक का क्षेत्र शामिल है।
5. सम्पूर्ण पूर्वी मध्यप्रदेश (चावल का प्रदेश) – इसमें रीवा, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट आदि जिले सम्मलित है।

जलवायु के आधार पर मध्यप्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रो में विभाजित किया गया है –

मध्य में कृषि विकास योजनाएँ एवं संस्थाएँ :-

1. **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना :-**

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा रबी 1999-2000 से क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों की वित्तीय सहायता दी जाती है।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - ⬇ (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न, 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न, 150 में से)

UP Police Constable 2024 - http://surl.li/rbfyn (98 प्रश्न, 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6URO

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

whatsapp - https://wa.link/dy0fu7 1 web.- https://bit.ly/3BGkwhu

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

whatsapp - https://wa.link/dy0fu7 2 web.- https://bit.ly/3BGkwhu

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
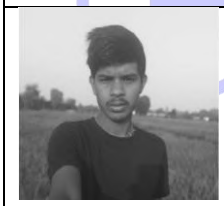	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota
	Sanjay	Haryana PCS	96379	Jind (Haryana)

And many others.....

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

WhatsApp करें - https://wa.link/dy0fu7

Online Order करें - https://bit.ly/3BGkwhu

Call करें - 9887809083

whatsapp - https://wa.link/dy0fu7 6 web.- https://bit.ly/3BGkwhu

FREE SAMPLE